



रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2005.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-43/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक-24) जो आज दिनांक 9 अगस्त, 2005 को

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) संक्षिप्त नाम। अधिनियम, 2005 है।

का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके धारा 269 का पश्चात् “मूल अधिनियम”, निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 269 की उप-धारा संशोधन। (3) में “ऐसे कनेक्शन के लिए”, शब्दों के पश्चात्, “गृह स्वामी या अधिभोगी भी सीवरेज कनेक्शन के लिए सरकार/नगर निगम द्वारा समय-समय पर यथा नियत किए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूज़र चार्जिज) का संदाय करेगा। गृह स्वामी या अधिभोगी द्वारा सीवरेज कनेक्शन लेने में लगातार व्यतिक्रम की दशा में या सरकार द्वारा यथा नियत प्रभार (चार्जिज) का संदाय करने में असफल रहने पर, नागरिक सुख सुविधाएं, अर्थात् जल, विद्युत इत्यादि को भी वियोजित किए जाने का दायी होगा”, शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 352 में, “तीन मास” और “पांच सौ” शब्दों धारा 352 का के स्थान पर क्रमशः “दो वर्ष” और “पांच हजार” शब्द रखे जाएंगे। संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगर निगम शिमला पर नगर निवासियों के लिए बुनियादी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने, और कानूनी कृत्यों का अनुपालन करने का दायित्व निहित है। नगर में मलवहन प्रणाली का सुधार करने के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। प्रणाली की कार्यचालन क्षमता हेतु आवश्यक है कि यह न तो उपयोगाधीन हो, न ही अनुपयोगी हो। प्रणाली के द्वारा मल वहन की अपर्याप्त निकासी प्रणाली के संचालन में कठिनाइयाँ पैदा करेगी। इसलिए अक्टूबर, 2004 में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में उपबन्ध किया गया जिसमें समस्त घरों के लिए सीवरेज कनेक्शन अनिवार्य किया गया। तथापि, यह पाया गया कि अभी भी लोग सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वे लगातार मलाशयों का प्रयोग कर रहे हैं। मलाशयों से बेकार जल का समुचित निपटान सुनिश्चित नहीं होता जिसके परिणामस्वरूप अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ पैदा हो कर स्वच्छता उपताप (न्यूसेंस) पैदा कर रही है, और भूगर्भ जल भी प्रदूषित होता है। इसलिए, शास्ति के उपबन्धों को अधिक कठोर बनाना आवश्यक हो गया है जैसे जल, विद्युत इत्यादि का वियोजन करना। इसके अतिरिक्त किसी वृक्ष इत्यादि को गिराने या गिराने के लिए दुष्प्रेरित करने से निपटने के लिए उपबंधित शास्ति पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है। शिमला के घने वनों को जिनका तीव्रता से ह्रास हो रहा है, सुरक्षित रखने के लिए और अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसे भारतीय वन अधिनियम के अधीन यथा विहित शास्ति के अनुरूप लाया जाना आवश्यक है, इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि शास्ति के उपबन्ध को अधिक कठोर बनाया जाए। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख.....2005.

वित्तीय ज्ञापन

शून्य

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए
विधेयक।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख....., 2005.

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) BILL, 2005**

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994).

(KAUL SINGH THAKUR),
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :
The , 2005.